

चीन ने क्षेत्रीय दावा करते हुए जारी किया मानचित्र

प्रलिस के लयि:

[अकसाई चनि क्षेत्र, नाइन-डैश लाइन, चीन-पाकसितान आर्थकि गलयारा \(CPEC\), वासुतवकि नयितरण रेखा \(LAC\)](#)

मेनुस के लयि:

चीन द्वाारा क्षेत्रीय दावा करते हुए जारी किया गया मानचित्र और भारत पर इसके प्रभाव

[स्रोत: द हट्टि](#)

चरुा में क्युँ?

चीन की सरकार ने हाल ही में वववादति क्षेत्रों पर अपने क्षेत्रीय दावों की पुषुट करिटे हुए "सुटैडरुड मैप ऑफ चाइना" का 2023 संसुकरण जारी कयिा ।

- यह मानचित्र चीन के "राषुटरीय मानचित्रण जागरूकता प्रचार सपुताह" के अनुरूप है, जो सटीक और सुसंगत मानचित्रण के महतुत्व पर ज़ोर देता है ।

नए मानचित्र में क्युा हैं चीनी दावे?

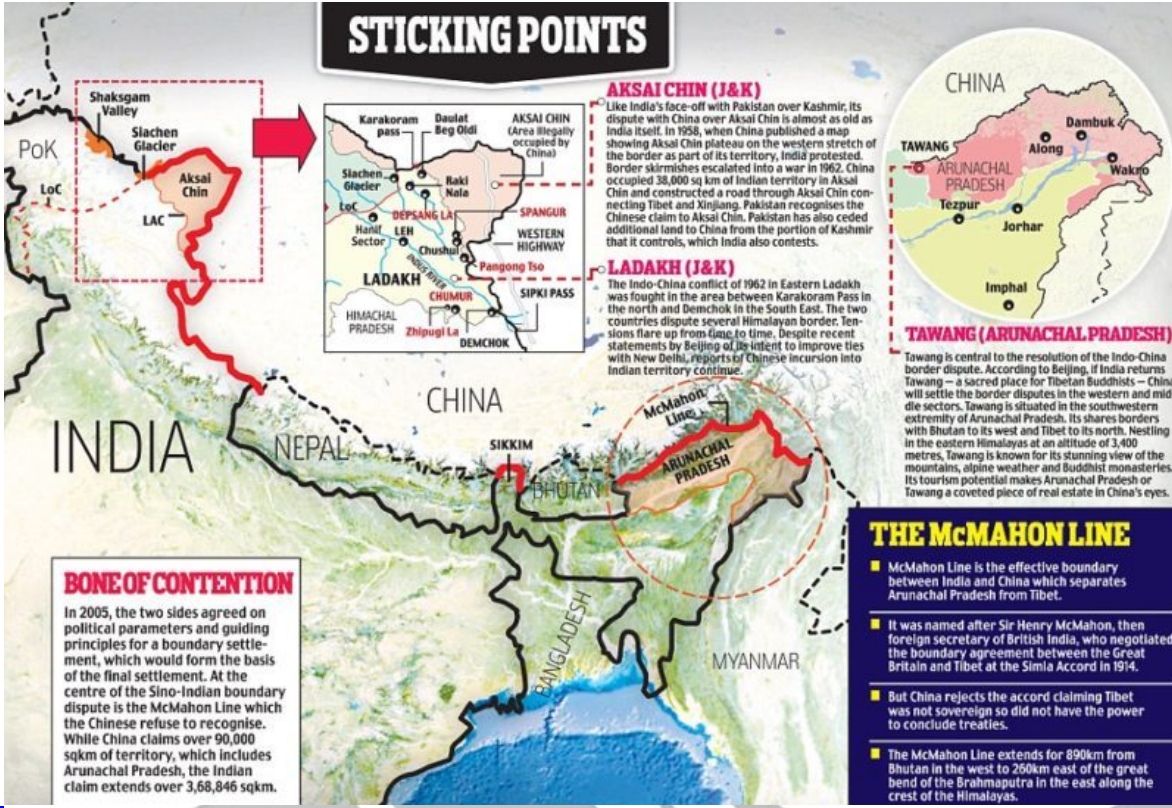
- क्षेत्रीय दावे:**
 - मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश और अकसाई चनि को चीन के हसुसे के रूप में दर्शाया गया है ।
 - ये दावे लंबे समय से चीन और भारत के बीच वववाद का मुददा रहे हैं ।
 - मानचित्र में "नाइन-डैश लाइन" भी शामिल है, जो एक वववादसुपद सीमांकन है, यह पूरे दकुषणि चीन सागर को कवर करती है और इस रणनीतकि समुदरी क्षेत्र पर बीजगि के दावों को रेखांकति करती है ।
 - मानचित्र में दसवीं-डैश लाइन को भी दर्शाया गया है जो ताइवान द्वीप पर बीजगि के दावों को रेखांकति करती है ।
- सुथानों का नाम बदलना:**
 - चीन का नया मानचित्र जारी करना उसकी पछिली कारुवाइयुँ के अनुरूप है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में सुथानों के नामों को मानकीकृत करना, जसिमें राज्य की राजधानी के करीब के क्षेत्र भी शामिल हैं ।
- डजिटल मैपगि:**
 - भौतकि मानचित्र के अलावा चीन सुथान-आधारति सेवाओं, सटीक कृषु, प्लेटफ़ॉर्म अरुथव्यवसुथा और इंटेलजेंट कनेकटेड व्हीकल सहति वभिन्नि अनुप्रयुगुँ हेतु डजिटल मानचित्र जारी करने के लयि तैयार है ।

भारत-चीन के बीच सीमा वववाद का मुददा

- पुषुठभूमि:**
 - भारत-चीन सीमा वववाद 3,488 कलिमीटर की साझा सीमा पर लंबे समय से चले आ रहे और जटलि क्षेत्रीय वववादों को संदरुभति करता है ।
 - वववाद के मुखुय क्षेत्र पशुचमी क्षेत्र में सुथति अकसाई चनि और पूरुवी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश हैं ।
 - अकसाई चनि:** चीन, अकसाई चनि को अपने शनिजयिांग क्षेत्र के हसुसे के रूप में दावा करता है, जबकि भारत इसे अपने केंदुरशासति प्रदेश लददाख का हसुसा मानता है । यह क्षेत्र चीन-पाकसितान आर्थकि गलयारे (CPEC) के नकिट होने और सैन्य मार्ग के रूप में इसकी कषुमता के कारण रणनीतकि महतुत्व रखता है ।
 - अरुणाचल प्रदेश:** चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश राज्य पर दावा करता है और इसे "दकुषणि तबिबत" कहता है । भारत इस क्षेत्र को पूरुवोत्तर राज्य के रूप में प्रशासति करता है तथा अपने क्षेत्र का अभन्नि अंग मानता है ।
- कोई स्पुष्ट सीमांकन नहीं:** भारत और चीन के बीच सीमा स्पुष्ट रूप से सीमांकति नहीं है और कुछ हसुसों पर कोई पारसुपरकि रूप से

सहमत वास्तविक नयित्करण रेखा (LAC) नहीं है।

- 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद LAC अस्तित्व में आई।
- भारत-चीन सीमा को तीन सेक्टरों में बाँटा गया है।
 - पश्चिमी क्षेत्र: लद्दाख
 - मध्य क्षेत्र: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड
 - पूर्वी क्षेत्र: अरुणाचल प्रदेश और सikkिम



■ सैन्य गतरिध:

- **1962 का भारत-चीन युद्ध:** सीमा विवाद के कारण कई सैन्य गतरिध और झड़पें हुईं, जिनमें **1962 का भारत-चीन युद्ध** भी शामिल है। दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न समझौतों और प्रोटोकॉल के साथ तनाव को प्रबंधित करने के प्रयास किये हैं।
- **हालिया झड़पें:** संघर्ष की सबसे गंभीर हालिया घटनाएँ वर्ष 2020 में **लद्दाख की गलवान घाटी** और वर्ष 2022 में अरुणाचल प्रदेश के **त्वांग** में हुई थीं।
 - पर्यवेक्षक इस बात से सहमत हैं कि सीमा के दोनों ओर वास्तविक नयित्करण रेखा (Line of Actual Control- LAC) पसर 2013 के बाद से गंभीर सैन्य टकराव की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

सीमा विवाद नपिटान तंत्र:

- **वर्ष 1914 का शमिला समझौता:** तिब्बत और पूर्वोत्तर भारत के बीच सीमा का सीमांकन करने के लिये वर्ष 1914 में शमिला में तीनों- तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।
 - चर्चा के बाद समझौते पर ब्रिटिश भारत और तिब्बत द्वारा हस्ताक्षर किये गए जबकि चीनी अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गए। वर्तमान में भारत इसे मान्यता देता है लेकिन चीन ने शमिला समझौते और मैकमोहन रेखा दोनों को अस्वीकार कर दिया है।
- **वर्ष 1954 का पंचशील समझौता:** पंचशील सन्धिघात ने स्पष्ट रूप से 'एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने' की इच्छा का संकेत दिया।
- **शांति और स्थिरता बनाए रखने पर समझौता:**
 - इस पर वर्ष 1993 में हस्ताक्षर किये गए थे, जिसमें बल के प्रयोग को त्यागने, LAC की मान्यता और बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दे के समाधान का आह्वान किया गया था।
- **LAC के सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली उपायों पर समझौता:**
 - इस पर वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किये गए थे, जिसमें LAC पर असहमतियों के समाधान के लिये गैर-आक्रामकता, बड़े सैन्य आंदोलनों की पूर्व

सूचना और मानचित्रों के आदान-प्रदान करने की प्रतबिद्धता व्यक्ति की गई थी।

- **सीमा रक्षा सहयोग समझौता:**
 - डेपसांग घाटी की घटना के बाद वर्ष 2013 में इस पर हस्ताक्षर किये गए थे।

चीन के नए मानचित्र का भारत पर प्रभाव:

- **प्रादेशिक दावा:**
 - विवादित क्षेत्रों को अपने आधिकारिक मानचित्र में शामिल करके चीन अपने क्षेत्रीय दावों को मज़बूत कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिनि पर भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है और सीमा विवाद को बढ़ा रहा है।
- **राजनयिक तनाव:**
 - चीन की हरकतों से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा हो सकता है। भारत ने लगातार चीन के क्षेत्रीय दावों को खारज़ि किया है और संभवतः अपने स्वयं के दावों की पुष्टि के साथ जवाब देगा।
- **द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव:**
 - यह भारत-चीन संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है, जिससे व्यापार, नविश और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग प्रभावित हो सकता है।
- **क्षेत्रीय संतुलन:**
 - सीमा विवाद का व्यापक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। यह चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिये अन्य देशों और क्षेत्रीय समूहों के साथ भारत के रणनीतिक संरक्षण को प्रभावित कर सकता है।

भारत को चीन की प्रादेशिक और क्षेत्रीय मुखरता से कैसे निपटना चाहिये?

- **कूटनीति और संवाद:**
 - भारत-चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता और परामर्श एवं समन्वय कार्य तंत्र (WMCC) जैसे स्थापित तंत्रों के माध्यम से चीन के साथ राजनयिक वार्ता में संलग्न रहने की आवश्यकता है।
 - शांतिपूर्ण समाधान, द्विपक्षीय समझौतों का पालन और सीमा पर शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के महत्त्व पर जोर देना चाहिये।
- **सीमा पर अवसंरचना की मज़बूत करना:**
 - भारतीय बलों के लिये गतिशीलता और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिये सड़कों, पुलों, हवाई पट्टियों और संचार नेटवर्क सहित सीमा अवसंरचना में बेहतर के लिये नविश करना चाहिये।
 - सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों और आपूर्ति की तेज़ी से तैनाती सुनिश्चित करने के लिये लॉजिस्टिक्स हब एवं अग्रवर्ती अड्डा (Forward Base) विकसित करना चाहिये।
- **सैन्य तैयारी बढ़ाना:**
 - सीमा क्षेत्र में प्रभावी ढंग से निगरानी करने और किसी भी घटना को लेकर प्रतिक्रिया देने के लिये उन्नत उपकरणों, प्रौद्योगिकी और निगरानी क्षमताओं में नविश करना चाहिये ताकि सशस्त्र बलों को मज़बूत बनाया जा सके।
 - सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के प्रशिक्षण और तत्परता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- **क्षेत्रीय एवं वैश्विक भागीदारी:**
 - समान विचारधारा वाले उन देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ साझेदारी को दृढ़ करना चाहिये जो क्षेत्रीय विवादों में चीन की मुखरता के बारे में चिंता साझा करते हैं।
 - गुप्त जानकारी साझा करने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और क्षेत्रीय चुनौतियों को लेकर समन्वित प्रतिक्रियाओं पर सहयोग करना चाहिये।
- **आर्थिक एवं व्यापारिक उपाय:**
 - चीन पर निर्भरता कम करने और आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लिये आर्थिक क्षेत्र में विविधता लाना चाहिये।
 - उन देशों के साथ व्यापार समझौतों और साझेदारी के बारे का पता लगाना चाहिये जो वैकल्पिक बाज़ार एवं नविश के अवसर प्रदान कर सकते हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय मंच:**
 - अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और संधिधार्तों पर आधारित शांतिपूर्ण समाधान के लिये समर्थन जुटाने हेतु अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सीमा मुद्दों को उठाना चाहिये।
 - क्षेत्रीय अखंडता और विवाद समाधान तंत्र से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानदंडों एवं संधिधार्तों को कायम रखना चाहिये।
 - सीमा मुद्दे पर भारत का कक्ष प्रस्तुत करने के लिये अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों के साथ जुड़ाव जारी रखना चाहिये।

नभिकर्ष:

- चीन द्वारा जारी मानक मानचित्र का 2023 संस्करण अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिनि क्षेत्र जैसे विवादित क्षेत्रों पर उसके क्षेत्रीय दावों की पुष्टि करता है।

- चीन का यह कदम राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में अपनी सीमाओं और भू-राजनीतिक हितों के प्रति उसके मुखर दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- यह मानचित्र अपने क्षेत्रीय दावों और भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिये चीन के प्रयासों के प्रतिबिंब के रूप में कार्य करता है।

संबंधित इन्फोग्राफिक्स: पड़ोसी देशों के साथ भारत के सीमा-विवाद

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. सियाचिनि हमिनद कहाँ स्थित है? (2020)

- (a) अकसाई चिनि के पूर्व में
- (b) लेह के पूर्व में
- (c) गलिंगति के उत्तर में
- (d) नुब्रा घाटी के उत्तर में

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- NJ9842 बटु के उत्तर-पूर्व में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है, जो सियाचिनि ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है।
- इसे ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर होने का गौरव प्राप्त है।
- यह अकसाई चिनि के पश्चिम में, नुब्रा घाटी के उत्तर में और गलिंगति के लगभग पूर्व में स्थित है।

अतः विकल्प (d) सही है।

??????:

प्रश्न. दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिये। (2016)